बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 116

मूल चिंता बरकरार

एयर इंडिया के लिए बॉन्ड बाजार से 22,000 करोड़ रुपये जुटाने की सरकार की योजना जोखिम से भरी हुई है। भारी भरकम धन जुटाने की योजना का व्यापक लक्ष्य इस सरकारी विमानन सेवा को बेचने के दूसरे प्रयास के पहले इसके लिए कुछ वित्तीय संसाधन जुटाने का है। घाटे में चल रही इस विमानन सेवा पर भारतीय और विदेशी ऋणदाताओं की 58,000 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। ऐसे में 7,000 करोड़ और 15,000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जुटाई जाने वाली उक्त राशि का इस्तेमाल बिना सरकारी बजट की मदद लिए कुछ कर्ज चुकाने में किया जाएगा। प्रथम दृष्टि में यह समझदारी भरा निर्णय लगता है क्योंकि विमानन कंपनी का कोई संभावित ग्राहक इस कर्ज का बोझ सहने को तैयार नहीं होगा।

परंतु तीन बातें इस कदम को लेकर संदेह पैदा करती हैं। पहला, चूंकि संभावित निवेशक 53,584 करोड़ रुपये के समेकित घाटे वाली कंपनी के बॉन्ड में कोई रुचि नहीं दिखाएंगे इसलिए सरकार ने इनके लिए सॉवरिन गारंटी देने का निर्णय लिया है। नब्बे के दशक में एनरॉन बिजली कंपनी का उदाहरण सॉवरिन गारंटी को लेकर सतर्कता बरतने की एक बड़ी वजह है। गहरे कर्ज में डूबी इस विमानन कंपनी के कर्ज के पुनर्गठन के कई प्रयास किए गए लेकिन नाकामी हाथ लगी। क्या वित्त वर्ष 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में 58 फीसदी ज्यादा शुद्ध घाटा सहन करने वाली कंपनी इन बॉन्ड के लिए तैयार है? यकीनन ऐसे वक्त जबकि अन्य विमानन सेवाएं जेट एयरवेज की विदाई से लाभान्वित हो रही हैं, एयर इंडिया कोई फायदा उठाने में नाकाम रही है। कंपनी के 15 विमान इसलिए जमीन पर खड़े हैं क्योंकि कंपनी कलपुर्जा बनाने वालों को भुगतान नहीं कर सकी है।

दूसरा, भारतीय बॉन्ड बाजार बहुत खोखला है और आईएलऐंडएफएस तथा अन्य डिफॉल्ट के बाद से उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बॉन्ड की पर्याप्त बिक्री न होने पर सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह जीवन बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि को इन बॉन्ड को खरीदने को कहेगी। यह एक परंपरा सी बन गई है। चूंकि दोनों संस्थान सरकारी हैं और सार्वजनिक कोष से चलते हैं इसलिए यह ऐसा ही होगा मानो सरकारी कंपनी ओएनजीसी, एक अन्य सरकारी कंपनी एचपीसीएल में निवेश करे। राजग सरकार ने वित्त वर्ष 2019 में ऐसे ही सौदों के जरिये विनिवेश का आंकड़ा सुधारा। सरकारी संस्थानों के बीच ऐसी चक्रीय व्यवस्था से एयर इंडिया की समस्या का तात्कालिक हल ही निकल सकता है। तीसरा, वित्त मंत्रालय ने एयर इंडिया से कहा है कि वह परिसंपत्तियों और अनुषंगियों की बिक्री से भुगतान की राशि जुटाए। कंपनी लंबे समय से अपनी कुछ अनुषंगियों की बिक्री का प्रयास कर रही है लेकिन नाकाम रही है।

यकीनन सरकार ने निजीकरण के पिछले प्रयास की नाकामी से सबक लिया है। यही कारण है कि वह इस बार बिक्री की शर्तों में सुधार को तैयार है। उसने प्रस्ताव रखा है कि नियमों को शिथिल बनाकर खरीदार को बिना समय सीमा के बंधन के शेयर बिक्री का अवसर दिया जाएगा। पहले तीन वर्ष की समय सीमा लगाई गई थी। इसके अलावा खरीदार के मौजूदा कारोबार में विलय या विपरीत विलय और विमानों की बिक्री या लीजबैक की सुविधा देने की बात भी शामिल है ताकि नया मालिक पूंजी जुटा सके। इसके अलावा सरकार बची हुई हिस्सेदारी भी नहीं रखेगी। यह नियम संभावित निवेशकों के लिए सबसे बड़ी बाधा था। ये शर्तें भले ही आकर्षक प्रतीत हो रही हों लेकिन ये विमानन कंपनी के परिचालन में निहित गहन ढांचागत समस्याओं को हल नहीं करतीं। जबकि संभावित खरीदार इन पर विचार करेगा। सरकार को पता लगेगा कि इन कदमों से समस्या केवल टल सकती है।

बिनय सिन्हा

बुर्जुआ, लोकलुभावनवाद और योग्यता का गणित

क्या योग्यता को वरीयता देने के नाम पर तमाम सुविधाओं को एक खास तबके तक सीमित कर दिया गया है? इस विषय का गंभीरता से विश्लेषण कर रहे हैं **अजित बालकृष्णन**

ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब कोई न कोई गंभीर विचारक बुर्जुआवाद, लोकलुभावनवादी या योग्य लोगों के शासन को लेकर अपनी राय प्रकट नहीं करता हो। ये विचार किसी अखबार के संपादकीय अथवा स्तंभ में प्रकाशित हो सकते हैं, किसी पत्रिका में या किसी वेबसाइट में। कई बार ये कार्यस्थल पर आपसी चर्चा में सामने आ सकते हैं तो कभी किसी मित्र के साथ शाम गुजारते हुए।

आइए एक नजर डालते हैं नाराजगी से भरी इस बातचीत की शब्दावली पर। 'खान मार्केट गैंग' (माना जाता है कि यह जुमला राजनीतिक परिवारों के उन युवा सांसदों के लिए गढ़ा गया जो संसद के भोजनावकाश में खान मार्केट स्थित महंगे रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते हैं लेकिन अब यह आर्थिक या सामाजिक रूप से वरीयता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है) 'लोकलुभावनवादी' (वंचित वर्ग के बड़े समूह को नकद या अन्य उपहारों के जरिये अपने साथ जोड़ने का हिमायती राजनैतिक वर्ग), 'धर्मनिरपेक्ष' (ऐसा व्यक्ति जो अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के अधिकार को सही मानता हो), 'छद्म धर्मनिरपेक्ष' (ऐसा व्यक्ति ढोंग के जरिये धार्मिक अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता हो), 'योग्यतावादी' (जो पदोन्नति से लेकर दाखिले तक में केवल योग्यता को वरीयता देने के हिमायती हों), 'आरक्षणवादी' (ऐसे लोग जो योग्यता के अलावा अन्य मानकों के हिमायती हों)...यह सूची बहुत लंबी है।

यह समझने के लिए बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है कि इन सभी शब्दों का इस्तेमाल निंदात्मक लहजे में किया जाता है। अगर आप किसी को खान मार्केट गैंग का सदस्य बताते हैं तो आप खुद को उससे अलग मानते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी को बुर्जुआ वर्ग का सदस्य बताते हैं तो आप खुद को उस वर्ग का नहीं मानते हैं।

शायद वक्त आ गया है कि बतौर भारतीय हमें यह आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से और आजादी के बाद आधी सदी में भी राजनीति, प्रशासन और कॉर्पोरेट जगत में बड़े पदों पर आसानी लोगों के बेटे और बेटियां ही वह जिम्मेदारी संभालते हैं? बड़े शहरों में रहने वाले और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई करने वालों को जीवन में इन उच्च पदों को प्राप्त करने में आसानी होती है?

अगर आप किसी गांव में पले बढ़े हैं और हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा के विद्यालय में पढ़े हैं तो जीवन में ऐसी सफलता पाने की संभावना सीमित है? अगर चुनावी वर्ष में इस तरह लोगों के नाम निकालने का सिलसिला चले तो आसानी से यह कहकर लोगों का दिमाग घुमाया जा सकता है कि चुनावों की गरमागरमी में ऐसी बातें हो जाती हैं और हमेशा इन बातों का मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि माहौल बदलने के साथ ही सभ्यता और सहयोग की संस्कृति वापस लौट आती है।

आखिरकार दुनिया की फिक्र करना, खासतौर पर उन लोगों की फिक्र करना जो आर्थिक रूप से हमसे कमजोर हैं, वह उदारता का परिचायक है और इसे लोकलुभावनवाद कहकर इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को हमेशा महंगे रेस्तरां में खाते-पीते देखते हैं तो आप मुस्करा कर स्वयं से यह कह सकते हैं कि वह एक अमीर आदमी है। आप हमेशा उसे बुर्जुआ कहकर नहीं पुकारते।

सन 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप की जीत के कारणों को समझने का प्रयास कर रहे विद्वानों का कहना है कि उनके मतदाता मोटे तौर पर श्वेत कामगार वर्ग के स्त्री-पुरुष थे। खासतौर पर ऐसे लोगों ने उन्हें वोट दिया जिन्होंने कॉलेज में शिक्षा तक नहीं ग्रहण की थी। इनमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग शामिल थे।

उनके मतदान की वजह स्पष्ट थी। उन्हें लगता था कि व्यवस्था और बुर्जुआ वर्ग द्वारा उनकी अनदेखी की गई है। ब्रिटेन में 2016 में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए किए गए मतदान में मिली चौंकाने वाली सफलता भी ब्रिटिश बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ जनता का रोष था। मतदाताओं ने अपनी अभिव्यक्ति में शायद यही कहा कि ब्रिटिश राजनेताओं, कारोबारी नेताओं और बौद्धिकों ने व्यवस्था पर नियंत्रण का अधिकार गंवा दिया है और बुर्जुआ वर्ग ने सामान्य लोगों के मूल्यों और हितों का अतिक्रमण किया है। इटली, हंगरी, पोलैंड, स्लोवेनिया और चेक गणराज्य में भी बुर्जुआ विरोधी नेता सत्ता में हैं।

कुछ पर्यवेक्षक इस बुर्जुआ विरोधी और लोकलुभावन समर्थक लहर को वैश्वीकरण की विचारधारा का प्रतिरोध मानते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पनपी और इसने ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। मौजूदा बुर्जुआ विरोधी आंदोलन की मान्यता है कि ऐसे संस्थान स्थानीय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और बड़े संस्थानों को अधिकार संपन्न बनाते हैं। इनका इस्तेमाल बड़े कारोबारियों के कॉर्पोरेट और वित्तीय हितों को पूरा करने, प्राकृतिक संसाधन जुटाने, आदि में किया जाता है।

भारतीय संदर्भ में देखें तो वैश्वीकरण से निर्मित इन संस्थानों में से किसी संस्थान में रोजगार पाना योग्यता के उन मानकों पर सफलता हासिल करना रहा है जिनमें कैट, जेईई एडवांस, जीआरई जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। हम मानते हैं कि युवाओं को उनके सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से परे शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलना चाहिए। इनमें आईआईएम, आईआईटी, नैशनल लॉ स्कूल और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं।

हमारा मानना रहा है कि ऐसे सरकारी संस्थान और ऐसी प्रवेश प्रक्रिया से ही हमारे दौर के शीर्ष पेशे सभी सामाजिक और आर्थिक वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे। ये केवल बुर्जुआ परिवारों के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा। परंतु इस बीच नए शोध लगातार यह बता रहे हैं कि इन परीक्षाओं के परिणाम में सामाजिक आर्थिक दर्जा मुखर होकर सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षित और प्रभावशाली माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा और महंगा ट्यूशन दिलाने में सक्षम हैं। यह इन परीक्षाओं को पास करने के लिए लगभग जरूरी हो गया है।

इसके अलावा इन संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया या सामूहिक चर्चा आदि में अच्छी अंग्रेजी बोलना आना आवश्यक है। कमजोर और वंचित तबके से आने वाले बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं।

इस संदर्भ में देखा जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह लोकलुभावन लहर नहीं बल्कि उस व्यवस्था में बदलाव का वोट हो जिसने योग्यता के नाम पर तमाम लाभ एक संकीर्ण अल्पांश समुदाय तक सीमित कर दिए हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था पर करना होगा नए सिरे से विचार

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

मैं एक अंधेरी और मैली नजर आ रही 'फैक्टरी' के भीतर हूं जहां प्लास्टिक के कचरे का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। इससे पहले मैंने जाकर यह देखा था कि हमारे घरों से आने वाले प्लास्टिक के कचरे को कैसे अलग-अलग किया जाता है और कैसे देश का गरीब तबका उसका कारोबार करता है। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित टिकरी में यह सब देखते हुए मैंने सवाल किया था कि यह प्लास्टिक कहां जाता है? मुझे बताया गया कि यह दिल्ली के औद्योगिक इलाके बवाना और नरेला में भेजा जाता है। इसके बाद मैं कई फैक्टरियों के बीच ऐसी फैक्टरी में आई थी जो इस कचरे को खरीदकर उसका पुनर्चक्रण करती है। यह एक भारी भरकम शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या है?

व्यापक तौर पर देखा जाए तो कुछ ऐसी तस्वीर बनती है: यह कचरा सावधानीपूर्वक अलग किया जाता है क्योंकि हर फैक्टरी केवल एक तरह के प्लास्टिक का प्रसंस्करण कर सकती है। पहले इसे अलग किया जाता है, फिर उबाला जाता है, गर्म किया जाता है और इसे तार के आकार में ढाला जाता है।

प्लास्टिक के इस तार को प्लास्टिक के दानों में परिवर्तित किया जाता है और अब इससे नए उत्पाद बनाए जाते हैं। यह काम करने वाले लोग गरीब हैं और उनकी काम करने की परिस्थितियां निहायत खराब। परंतु वे अपनी आजीविका के लिए ऐसे कारोबार में शामिल हैं जो कचरे से संसाधन जुटाता है। हमें उनके प्रयास को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगर इस कचरे का प्रसंस्करण नहीं किया जाता तो इसे खुले में जलाया जाता या इससे कचरे के ढेर बनते। बवाना जैसी जगहों ने हमें बचा रखा है।

इस व्यापार का अर्थशास्त्र तभी कारगर होता है जब गरीबों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को कमतर आंका जाता है। सन 1991 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री लैरी समर्स ने यह हिमायत की थी कि विषाक्त कचरे और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों को अल्प विकसित देशों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। समर्स बाद में हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, उनकी इस बयान के लिए काफी आलोचना भी की गई लेकिन आखिरकार वह सही साबित हुए। दुनिया भर में यह सिलसिला चल निकला। तमाम प्रमुख देशों ने अपनी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियां गरीब देशों में स्थानांतरित कीं और वहां कचरे के पहाड़ खड़े कर दिए। यह सब व्यापार और गरीबों की आजीविका के नाम पर किया गया।

आखिरकार चीन ने 2018 में प्लास्टिक कचरे का आयात बंद किया। अब नए बाजारों की तलाश थी। मलेशिया और इंडोनेशिया समेत तमाम नए देश स्वेच्छा से आगे आए। परंतु प्लास्टिक कचरा ऐसे ठिकाने खोजता रहा जहां पुनर्चक्रण सस्ता हो और स्थानीय कारोबारों को लाभान्वित कर यह रोजगार मुहैया कराए। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक विश्व है। समर्स का कहना सही साबित हुआ।

यह अलग बात है कि विकसित देशों का कचरा संभालने वाले ये सारे देश अपने ही कचरे से जूझ रहे हैं। सच तो यह है कि अगर अमीर देश पुनर्चक्रण की असली कीमत चुका सकते तो वे भी अपना कचरा गरीब देशों में नहीं भेजते। पूरा मामला लागत कम करने का है। यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मई 2019 में बेसल सम्मेलन की बैठक में पहली बार प्लास्टिक कचरे को उस समझौते में शामिल किया गया जो तमाम देशों को पारंपरिक कचरे में उत्पन्न हानिकारक तत्त्वों के लिए जवाबदेह ठहराता है। इसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। नॉर्वे ने एक खास किस्म के प्लास्टिक के कारोबार को नियमित करने के लिए संशोधन किए जिसका अमेरिका ने तगड़ा प्रतिवाद किया और आखिरकार काफी शिथिल करने के बाद इस बात पर सहमति बनी कि संक्रमित प्लास्टिक कचरे और तथाकथित स्वच्छ प्लास्टिक कचरे के बीच भेद किया जाएगा। स्वच्छ प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस प्रकार कुछ नियंत्रण कायम हुआ लेकिन यह कारोबार जारी रहेगा और समर्स का सिद्धांत भी लागू रहेगा।

सवाल यह है कि क्या यही हमारा भविष्य है? कचरा संसाधन हो सकता है लेकिन यह भी साफ है कि हमें यथासंभव इसका पुनर्चक्रण और जितनी बार संभव हो दोबारा इस्तेमाल करना होगा। बेसल समझौता हानिकारक उत्पादों का अवैध कारोबार रोकने में सहायक हो सकता है लेकिन यह कचरे के कारोबार, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण की भी इजाजत देता है। पुनर्चक्रण की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा केवल वहीं होगा जहां लागत कम होगी और जहां पर्यावरण तथा स्वास्थ्य मानक शिथिल होंगे।

मामला केवल प्लास्टिक और अमीरों के हित का नहीं है। यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक कचरे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उसने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निर्यात की इजाजत भी चाही है। अफ्रीका के देशों में पुराने कपड़े और कारें खपाई जा रही हैं। यह सब परोपकार के नाम पर किया जा रहा है। इससे एक नए तरह का स्थानीय कारोबारी हित तैयार हो रहा है। यह कचरे का कारोबार करना चाहता है। यही उनका कारोबार है।

अब समय आ गया है कि हम कचरे के इस कारोबार पर नए सिरे से विचार करें। हमें अपना कचरा खुद निपटाने पर विचार करना होगा। हर शहर को प्रसंस्करण समेत अपने कचरे का प्रबंधन करना चाहिए। ऐसा करके ही हम कचरा उत्पादित करने और उसके पुनर्चक्रण को लेकर अधिक जिम्मेदार हो पाएंगे। हमें इसके लिए इस चक्रीय अर्थव्यवस्था पर लगाम लगानी होगी। इसके लिए हमें कोई स्थायी तरीका तलाश करना होगा।

कानाफूसी

चेन्नई में पानी पर बवाल

चेन्नई में जल संकट गहराने के बाद कई लोगों ने उसे मार्केटिंग का औजार भी बना लिया है। एक ओर जहां पानी को लेकर शहर में झगड़े की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं कुछ लोग इस संकट का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं। यहां एक बाल्टी पानी की कीमत 25 रुपये तक पहुंच गई है। ऐसे में कुछ दुकानों ने इडली या डोसे का एक किलो घोल खरीदने पर बाल्टी पानी देना शुरू कर दिया है। वे ग्राहकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे बाल्टी लेकर आएं और घोल के साथ पानी ले जाएं। कई परिवार रेस्तरां में खाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि खाना पकाने या बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है। इस मसले पर द्रमुक के संभावित हमले से तैयार रहने के लिए अन्नाद्रमुक ने अपने सभी सदस्यों को कहा है कि वे सत्र के दौरान उपस्थित रहें। पार्टी इस विषय पर गंभीर दिखना चाहती है।

हेल्पलाइन को चाहिए मदद

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने बहुत जोरशोर से सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। 2014 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंदीदा योजनाओं में से एक बताया जाता था। इस हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार आम जनता की तकलीफों को दूर करने का प्रयास करती है। बहरहाल, ताजा जानकारी के मुताबिक अब हेल्पलाइन के पास विभिन्न सरकारी विभागों की करीब 3 लाख से अधिक शिकायतें निराकरण के लिए लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक 45,000 शिकायतें राजस्व विभाग की हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश लंबित शिकायतें प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार आने के बाद पंजीकृत की गई हैं। उनका कहना है कि नई सरकार की इस योजना में बहुत अधिक रुचि नहीं दिख रही है, इसलिए मामले लंबित हैं।

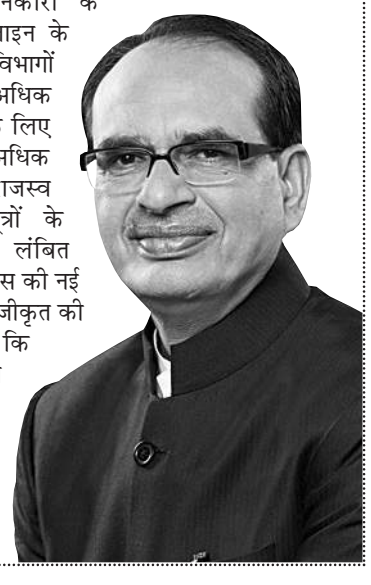

आपका पक्ष

जल संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी

देश के कई क्षेत्रों से पानी की कमी की खबरें आ रही हैं। अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि बड़े पंप भी पानी नहीं खींच पा रहे हैं। चेन्नई में जलसंकट काफी गहरा गया है जिसे दूर करने के लिए दूसरे राज्यों से पानी के टैंकर मंगवाए जा रहे हैं। इसका फायदा कुछ पानी टैंकर वाले उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल 40 प्रतिशत से अधिक पानी की कमी है। यह समस्या अचानक उत्पन्न नहीं हुई है। यह मनुष्य की विलासिता वाली जिंदगी के कई वर्षों का परिणाम है। देश में बुनियादी ढांचा और विकास के नाम पर जिस तरह पर्यावरण की बलि चढ़ाई जा रही है, उससे धरती अपनी नमी खोती जा रही है। इससे गर्मी में तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कई कंपनियां बोतलबंद पानी बेच रही हैं। पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया में 60 प्रतिशत पानी बेकार हो जाता है।

चेन्नई में इस साल पुझल जलाशय सूखने के कगार पर पहुंच गया -पीटीआई

यह आंकड़ा सिर्फ एक छोटे से संयंत्र का है। अगर जल्द ही ऐसे संयंत्र पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थिति और खराब हो जाएगी। वहीं बारिश के पानी को जमा करने से भी पानी की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल सकती है। लेकिन देश में अधिकतर तालाब, नदियां कूड़े से पाट दिया गया है और इसकी संख्या भी घटती ही जा रही है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश का पानी जमा किया जा सकता है। सरकार को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पानी की बरबादी रोकने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर साल देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शायद जल्द ही हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएं। जाहिर है पानी की कमी पर बढ़ती जनसंख्या का भी प्रभाव है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी अधिक पानी की जरूरत होगी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के साथ-साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है।

शुभम शर्मा, नोएडा

आतंक पर भारी श्रद्धा

अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए पहला जत्था रवाना किया गया है। पहले जत्थे में करीब 2 हजार श्रद्धालु हैं तथा अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे देश से करीब डेढ़ लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। अमरनाथ तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सेना तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अमरनाथ यात्रा अनंतनाग जिले के 36 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और गांदेरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से होती है। इस साल भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ऐसे में आतंकवादी यात्रा में विघ्न डालने का प्रयास कर सकते हैं। हाल में श्रीलंका में एक धर्म विशेष के धार्मिक समारोह में आतंकियों ने हमला किया था जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। इसके मद्देनजर भी अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लिया था। सरकार घाटी में शांति बहाल करने के लिए कई प्रयास कर रही है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।